मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

मैच के बहाने क्रिकेट व्यवसाय पर विधायक की नज़र
मोदी और गणतंत्र दिवस — 3

जन धन में खाता खुलवाना है
पुलिसिया दमन के खिलाफ़ छात्र आंदोलन — 5

भूमि अधिग्रहण कानून में फेरबदल क्यों ?
लोक से दूर होता 'लोकतंत्र' — 6

हुड्डा को नहीं भाया, खट्टर को ईमानदारी ने सताया
सफ़ाई तो सफ़ाईकर्मी ही कर सकते हैं फ़ोटो सेशन नहीं — 8

वर्ष 28 | अंक 4 | फरीदाबाद, वीरवार, 1-15 जनवरी 2015 | फोन : - 9999595632 | 2 ₹

मंथर गति से चल रहा वर्षों पुराना फ़रीदाबाद 6-लेन प्रोजेक्ट

कैग ने बताया अनिल अम्बानी को जालसाज, धोखेबाज

मज़दूर मोर्चा में दिल्ली-आगरा राजमार्ग को 6-लेन बनाने में अनिल अम्बानी द्वारा सरकारी मिलीभगत से धोखाधड़ी एवं जालससाजी के वृतांत दिये जाते रहे हैं। अब कैग की रिपोर्ट ने भी इन आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि कर दी है। फ़रीदाबाद से होकर गुजरने वाले इस राजमार्ग का निर्माण वर्षों पीछे चल रहा है और केन्द्र व राज्य सरकारें जनता की इस खुली लूट की जुगाली में मस्त हैं। पूंजीशाहों पर आपराधिक मुकदमे चलाने का रिवाज भारत में 'कानून के शासन' का हिस्सा नहीं बन सका है।

मजदूर मोर्चा, फरीदाबाद ब्यूरो

अनिल अम्बानी की कम्पनी रिलांयस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने आगरा-दिल्ली और पुणे-सतारा राजमार्गों में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही जनता से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी। यही नहीं, इस धन को अनिल ने अपनी अन्य कम्पनी के म्यूचुअल फंड में लगा दिया। यह सब करने के लिए सड़क निर्माण से सम्बन्धित जाली दस्तावेज बनाये गये जिनमें फ़र्जीतौर पर मशीनरी और कर्मचारी साइट पर काम में लगे दिखाये गये। यह खुलासा भारत के महालेखा परीक्षक (कैग) की संसद के समक्ष प्रस्तुत होने वाली रिपोर्ट में किया गया है।

अनिल की रिलांयस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिल्ली-आगरा राजमार्ग पर जगह-जगह टोल बैरियर लगा कर 16 अक्टूबर, 2012 से राहगीरों की जेब काटनी शुरू कर दी थी जबकि 27 जून, 2013 तक पहला माइलस्टोन का काम भी शुरू नहीं हो सका था। 27 जून, 2013 की तारीख इस लिये महत्वपूर्ण है कि करार अनुसार इस तारीख तक पहले माइलस्टोन का काम पूरा हो जाना चाहिये था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार अनिल की इस कम्पनी ने दिल्ली-आगरा राजमार्ग पर वसूले 120 करोड़ में से 78 करोड़ रुपये अपने म्यूचुअल फ़ंड में लगा दिये। इसी तरह कम्पनी ने पुणे-सतारा राजमार्ग पर वसूले 542 करोड़ में से 225 करोड़ भी उपरोक्त म्यूचुअल फ़ंड में डाल दिये।

ऐसी आपराधिक धोखाधड़ी और जालसाज़ी के बावजूद न तो केन्द्र सरकार ने और न ही सम्बन्धित राज्य सरकारों ने अनिल अम्बानी और उसकी कम्पनी के विरुद्ध कोई कदम उठाया है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि तमाम सरकारें चलाने वाले पूंजीशाहों के टुकड़ों पर खुद तो पलते ही हैं, राजनीतिक गिरोहों का संचालन भी इसी फंड से होता है। यदि एक सामान्य नागरिक चन्द हज़ार रुपयों की भी अमानत में खयानत कर दे या झूठा आठवीं दर्जे का शैक्षिक प्रमाणपत्र ही बना लें तो उसका जेल जाना तय है। पर पूंजीशाहों के ऐसे ही लाखों गुणा बड़े कारनामे भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखे जाते। लिहाजा कैग रिपोर्ट पर शायद ही कोई कार्यवाही हो।

कैग ने अपनी छान-बीन में यह भी पाया कि देश में इस तरह के बीस 6-लेन प्रोजेक्ट की जमानत राशि का 902 करोड़ रुपया भी सम्बन्धित निजी कम्पनियां अपने अन्य धंधों में लगा चुकी हैं। यह जमानत की रकम सरकार के पास जमा रहनी चाहिये थी ताकि निर्धारित समय पर काम के विभिन्न चरण पूरे न होने पर करार के अनुसार जुर्माना वसूली की जा सके। जाहिर है, इस रकम कों कम्पनियों द्वारा डकारना तभी संभव हो सका जब केन्द्र सरकार के राजमार्ग मन्त्रालय की ठेका उठाने वाली कम्पनियों से मिलीभगत हो। कानून-कायदे से अनिल अम्बानी जैसों के साथ-साथ सम्बन्धित सरकारों के अधिकारियों व मन्त्रियों की आपराधिक जिम्मेदारी भी बनाई जानी चाहिये। पर क्या ऐसा होगा? केन्द्र में मोदी सरकार का फ़लसफ़ा तो यह है कि पूंजीशाहों को खुली छूट होनी चाहिये, अन्यथा देश में पूंजी-निवेश का वातावरण बिगड़ जायेगा।

100 करोड़ मैट्रो रेल से हड़पना चाहता था अम्बानी

लूट का माल हड़पने के आदी अनिल अम्बानी ने फ़रीदाबाद में होने वाले मैट्रो रेल निर्माण से भी 100 करोड़ रुपये मुफ़्त में हड़पने की पूरी कोशिश की थी। इसी कोशिश में मैटो रेल का निर्माण कार्य महीनों देरी से शुरू हो पाया था।

तमाशा यह था कि मैट्रो रेल से पहले 6-लेन काम का ठेका अनिल अम्बानी को मिल चुका था। इसलिये राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मैट्रो रेल को मिलने वाले एन ओ सी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) में अनावश्यक रूप से देरी की गयी। कभी कहा गया कि राजमार्ग के बाईं और मैट्रो रेल निर्माण करे कभी बीच में तो कभी दायें ओर। तर्क यह था कि इस मैट्रो निर्माण से अनिल को 6-लेन का काम करने में भारी दिक्कतें होंगी। अन्त में इन्हीं दिक्कतों को आधार बताकर राजमार्ग प्राधिकरण ने एनओ सी देने के बदले मैट्रो रेल से 100 करोड़ रुपये मांग लिये थे। मैट्रो रेल द्वारा साफ़ इन्कार कर दिये जाने तथा 100 करोड़ की मांग को हरियाणा सरकार की ओर धकेल दिये जाने के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गयी तथा अपनी पुलिस के बल पर मैट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू कराया।

दोहरा टोल टैक्स: निर्वाचन क्षेत्र को खट्टर का तोहफ़ा

करनाल शहर से विधायक निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर के 'सुशासन' के तोहफ़े क्षेत्र की जनता को मिलने शुरू हो गये हैं। करनाल से पानीपत के बीच में पहले एक अपेक्षाकृत छोटा टोल बैरियर हुआ करता था। अब, मुख्यमंत्री बनते ही खट्टर ने एक और चार गुणा बड़ा टोल बैरियर लोग़ों के सिर पर लाद दिया है। पहले वाला बैरियर पानीपत शहर में घुसने के एन पहले था तो अब दूसरा घरोंडा में घुसने से पहले लगा दिया गया है। यानी अगर कोई करनालवासी 15 किलोमीटर दूर घरोंडा भी जा रहा हो तो 100-150 रुपये की चपत तो उसे लगेगी ही । ये दोनों बैरियर बमुश्किल 25 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमानुसार ऐसे दो बैरियरों के बीच कम से कम 50 किलोमीटर का फासला तो हाना ही चाहिये।

तुर्रा यह है कि जिस राजमार्ग के बिस्तार के नाम पर यह वसूली की जा रही है, उसका काम वर्षों पीछे चल रहा है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बावजूद काम की रफ़्तार चींटी की गति से आगे नहीं बढ सकी है। यूं तो पिछली हुड्डा सरकार द्वारा बिना सड़क निर्माण पूरा किये ही टोल वसूली की अनुमति देना जनता के साथ एक आपराधिक धोखा-धड़ी ही था। अब सम्बन्धित कम्पनी द्वारा काम में लागातार कोताही के बावजूद, खट्टर सरकार द्वारा उसकी लूट को और बढावा देना कहीं बड़ी आपराधिक साजिश ही माना जायेगा। जानकारों का कहना है कि इसी सड़क पर एक और बैरियरअम्बाला से पहले लगाये जाने की योजना है ताकि अम्बाला व चंडीगढ जाने वाले लोगों की जेबें भी काटी जा सकें।

जाहिर है जब खट्टर अपने निर्वाचन क्षेत्र करनाल के वासियों को नहीं बख्श रहे तो अपने वरिष्ठ मन्त्रीमंडल सहयोगी अनिल विज को क्या बख्शेंगे। यह भी स्पष्ट है कि बिना लेन देन की ऐसी मोटी लूट सम्बन्धित कम्पनी अकेले तो नहीं मचा सकती। यह भी तब हो रहा है जब केन्द्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी ने बार-बार यह बयान दिया है कि राजमार्ग बनने से पूर्व टोल टैक्स की वसूली किया जाना ग़लत है। यहां तक कि मोदी सरकार इस मामले में एक बिल लाने पर भी विचार कर रही है। जब तक जनता की सरेआम लुटाई पर 'विचार' चल रहा है, खट्टर की मिलीभगत से करनालवासी अपनी जेबें कटवाते रहेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से अपने निर्वाचन क्षेत्र को अगर ऐसे ही तोहफ़े मिलते रहे तो अगले चुनाव में उन्हें कहीं हार का तोहफ़ा न कबूलना पड़े।

दिलचस्प बात यह है कि पानीपत से जालंधर तक की इस 6-लेन प्रयोजना की कुल लागत 2288 करोड़ रुपये तय हुई थी लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक निजी कम्पनी सोमा आइसोलक्स से सांठ-गांठ करके इस लागत को 3779 करोड़ रुपये कर दिया है। अभी देखना यह है कि परियोजना पूरी होते तक यह लागत कितनी पहुंचेगी।

ख़बर दार

मोदी का अस्सी घाट गुणगान मानो राम का लंका अभियान

25 दिसम्बर प्रधानमत्री मोदी बनारस के अस्सी घाट पर क्या पहुंचे भारतीय मीडिया को मानो खुशामदी होड़ का नायाब मौका मिल गया। सारा दिन तथाकथित राष्ट्रीय टीवी चैनल मोदी के झाड़ू ड्रामें की डुगडुगी बजाते रहे। लगता था जैसे भगवान राम ने लंका फ़तह कर ली हो और सारी अयोध्या खुशी में नाच रही है।

हुआ सिर्फ़ इतना ही था कि मोदी ने झाड़ू पकड़ कर फ़ोटो सेशन की औपचारिकता पूरी की थी। साथ ही, उनके आने से पहले नगर निगम व स्थानीय प्रशासन ने मिल कर अस्सी घाट की वी आई पी सीढियों की मिट्टी हटा दी थी, जिससे बरसों से दबी सीढियां बाहर निकल आइ थीं।

चुनाव जीतने के बाद मोदी ने अपने पहले भाषण में बनारसवासियों से घाटों की सफ़ाई का आह्वान किया था। उसी को याद करते हुए मोदी ने इस अवसर पर दावा किया कि यह सफ़ाई बनारसवासियों द्वारा उनके बताये रास्ते पर चलने का नतीज़ा है। लगे हाथों मोदी ने तमाम एन जी ओ और मीडिया घरानों समेत नामचीन हस्तियों को भी प्रशंसा के इसी दायरे में लपेट लिया।

कमाल तो मीडिया का है। मोदी भक्तों का ऐसा परदा तमाम चैनलों व अख़बारों पर चढा हुआ है कि वे भी मोदी के प्रशस्तिगान गाने में ही लगे रहे। एक-आध अपवाद को छोड़कर किसी ने भी यह जांचने की समझ नहीं दिखाई कि जो काम नगर निगम का एक जे ई 15 दिन में कर सकता था उसके लिये स्वयं प्रधानमंत्री को दो बार अस्सी घाट पर आने की क्या जरूरत पड़ गयी? लगता है कि अगर इस देश के प्रशासनिक शून्य में पत्ता भी हिल जाय तो उसका श्रेय भी मोदी के खाते में ही दर्ज होगा। विडम्बना यह कि 25 दिसम्बर को भी केवल उन रास्तों व स्थानों को छोड़ कर, जहां मोदी का काफ़िला पहुंचा, शेष बनारस में गंदगी ज्यों की त्यों बजबजाती रही। हां, मोदी की तर्ज पर जगह-जगह औरों ने भी फ़ोटो सेशन कराये।

25 दिसम्बर को मोदी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस घोषित किया था। पर बनारस में ही नहीं सारे देश में सुशासन के नाम पर 'झाड़ू पकड़ो फ़ोटो खिंचाओ' अभियान ही चलता रहा। हर गंभीर से गंभीर मुद्दे को नारा बना देने वाले मोदी और उनके चेले-चाटों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? भगवान राम ने भी लंका जीतने में धनुष-बाण और सेना का प्रयोग किया था। मोदी ने यह यश झाड़ू और मीडिया के सहयोग से हासिल कर लिया। फ़र्क इतना ही है कि भगवान राम ने दुष्टों का समूल नाश कर दिया था, जबकि मोदी के झाड़ू रास्ते से देश की तो क्या बनारस की भी गंदगी खत्म होने वाली नहीं।